

# सृष्टि एग्रो



भारतीय कृषि बीमा की वर्तमान स्थिति

वर्ष : 2 अंक - 02

मुंबई, 16 फरवरी से 28 फरवरी 2014

मुल्य-2/- रुपए पृष्ठ-8

ग्रामीण विकास का संपूर्ण पाक्षिक समाचार पत्र

## कृषि वसंत से देश में दूसरी अनाज उत्पादन रहेगा 26.32 करोड़ टन: शरद पवार

### हरित क्रांति : राष्ट्रपति

नागपुर. राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने यहां कहा कि कृषि वसंत से देश में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत होगी। उन्होंने देश की सकल घरेलू विकास दर बढ़ाने के लिए कृषि व उद्योग सेक्टर को मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। वे यहां राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी 'कृषि वसंत' के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। वर्धा मार्ग पर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी 'कृषि वसंत' का उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों ही हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि विकास का सीधा संबंध देश के विकास से है।



विखे पाटील, नागपुर के पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, संपर्क मंत्री अनिल देशमुख, राज्य के मुख्य सचिव जे.एस. सहारिया आदि प्रमुखता से मंच पर उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेश के कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने भी अपने विचार रखे। केंद्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने प्रस्तावना रखी। प्रदर्शनी का आयोजन केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने किया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, भारतीय उद्योग महासंघ भी सहभागी हैं।

एक प्रतिशत कृषि विकास बड़े पर 4 प्रतिशत रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि वसंत के आयोजन से देश के कृषि विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल के. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार, भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेश के कृषि मंत्री राधाकृष्ण

सरकार, भारतीय उद्योग महासंघ भी सहभागी हैं।

मुंबई देश का खाद्यान्न उत्पादन इस साल 26.32 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। कृषि मंत्री शरद पवार ने आज यह बात कही। इससे पहले खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन दो साल पहले 25.9 करोड़ टन रहा था। पवार ने यहां एक कृषि सम्मेलन में कहा, 'देश इस साल 26.32 करोड़ टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल कर सकता है। यह दो साल पहले के 25.9 करोड़ टन से करीब 40 लाख टन अधिक होगा।' पिछले फसल वर्ष (जुलाई-जून) के दौरान खाद्यान्न उत्पादन मामूली घटकर 25.53 करोड़ टन रहा था। देश के कुछ हिस्सों में सूखे की वजह से खाद्यान्न उत्पादन घटा था। बेहतर मौसम और खरीफ (गमियों) व रबी (सदियों) फसलों की बुआई बढ़े से इस साल खाद्यान्न उत्पादन की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। पवार ने कृषि क्षेत्र की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत इस समय दुनिया के शीर्ष चावल उत्पादक के रूप में उभरकर सामने आया है। वहीं गेहूं व कपास निर्यात के मामले में वह दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भारत दूध व बागवानी फसलों के शीर्ष उत्पादक के रूप में उभरा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने हाल में जारी चालू वित्त वर्ष के अपने अग्रिम अनुमान में कृषि एवं संबन्धित क्षेत्रों की वृद्धि दर 4.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 1.4 फीसदी रही थी। पांच दिन के इस सम्मेलन 'कृषि वसंत' का आयोजन केंद्र और महाराष्ट्र ने उद्योग संगठन सीआईआई के साथ किया है। गेहूं व कपास के आयात पर निर्भर नहीं भारत केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि



गेहूं और कपास के निर्यात से देश को 2.32 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।

### कलावती के गांव के किसान ने की आत्महत्या

यवातमल (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में आने वाले जालका गांव में एक कर्ज के बोझ तले दबे एक किसान ने कथित तौर पर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह वही गांव है, जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कलावती नामक महिला से 2009 में मिले थे। कलावती के पति ने कर्ज से तंग आकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। राहुल के इस दौर को बहुत प्रचार मिला था।

### सौर ऊर्जा से निकाला गन्ने का रस

नागपुर प्रदर्शनी में रिकेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की गन्ने का रस निकालने वाली सोलर मशीन लोगों को अद्भुत लगी। सौर ऊर्जा से चलने वाली यह मशीन चंद सेकंड में गन्ने का रस (शेष पृष्ठ 2 पर)

### अठारह लाख किसानों को मिले सॉयल हेल्थ कार्ड

चंडीगढ़... हरियाणा कृषि विभाग द्वारा अब तक 17.87 लाख किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य) जारी किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया गया है, जिसे किसानों द्वारा कहीं से भी देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। हरियाणा मिट्टी की उर्वरता की मैपिंग करने के मामले में देश का आदर्श राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत, प्रदेश में प्रत्येक गांव की मिट्टी की उर्वरता की मैपिंग की गई है तथा इससे संबंधित आंकड़ों को ऑनलाइन किया गया है। विभाग द्वारा मृदा उर्वरता की मैपिंग के अलावा मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। विभाग द्वारा मृदा उर्वरता को फिर से बहाल करने के लिए किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों, जिंक सल्फेट, फैंट सल्फेट तथा मैगनीज सल्फेट पर 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। शारीय मिट्टी में सुधार तथा सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम द्वारा 60 प्रतिशत सब्सिडी दरों पर जिप्सम उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिप्सम उपयोग के लिए 4,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लक्षित रखा गया है तथा इस कार्य के लिए 12.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। (शेष पृष्ठ 2 पर)

### मुंबई में होगी पेड़ों की गिनती!

मुंबई दो साल की देरी के बाद आखिरकार बीएमसी पेड़ों की गिनती शुरू करने जा रहे हैं। प्रशासन चर्चों में स्थित ओवल मैदान से गिनती शुरू करेगी। बीएमसी पहले बार पेड़ों की गिनती में जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। पिछली बार पांच साल पहले पेड़ों की गिनती हुई थी तो मुंबई में कुल 19 लाख पेड़ थे। बीएमसी सरकारी इलाकों, आरि कॉलोनी, संजय गांधी नेशनल पार्क और मैग्रोव के पेड़ों को इस गिनती में शामिल नहीं करेगी।

### तहसील व विकास खण्डस्तर पर संवादाताओं की आवश्यकता

मुंबई से प्रकाशित प्रमुख हिन्दी कृषि पक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एग्रो उपरोक्त राज्य के विकास खंड एंव तहसील स्तर पर संवादाता नियुक्त करने है। संवादाता बनने के लिए कृषि विकास की जानकारी एंव ग्रामीण कृषि से सम्बन्धित होना अति आवश्यक है। कृषि विषय के जानकार व कृषि आदान से जुड़े व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। संवादाता की नियुक्ति कमीशन आधार पर होगी, संवादाता का मुख्य कार्य सृष्टि एग्रो के अधिक से अधिक सदस्य बनाना व विज्ञापन लेना रहेगा। अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखना, व उसका समाचार सृष्टि एग्रो में भेजना प्रमुख दायित्व में शामिल रहेगा अगर आप उपरोक्त शर्तों से सहमत हैं तो सृष्टि एग्रो से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें।

022-66998360/61.  
Fax: 022-66450908,  
info@srushtiagroneews.com

### सौइलैस गार्डनिंग कॉन्फ्रेंस व मिनी एक्सपो. सफलतापूर्वक संपन्न



मुंबई सौइलैस गार्डनिंग कॉन्फ्रेंस व मिनी एक्सपो. सफलतापूर्वक संपन्न हुआ! ऐसे आयोजनों से आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा यह कहना था आयोजक आदित्य चौधरी का, सृष्टि एग्रो ने सौइलैस गार्डनिंग कॉन्फ्रेंस व मिनी एक्सपो. में भाग लिया

### भरोसे का साथ विश्वास की बात

विप सिंचाई दुनिया के लिए नेटाफिम की देन है और 30 साल के अनुभव से संपन्न यह कंपनी 110 देशों में सिंचन संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही है। हमारी जिम्मेदारी विप सिंचन उपकरण के डिज़ी पश्चात खत्म नहीं हो जाती है। हम सिंचन का संयोजन, रखरखाव, सिंचन तथा खाद व्यवस्थापन, और आवश्यक कृषिसेवा अपने किसानों को प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराते हैं।

इसीलिए विश्व के 110 देशों के किसान नेटाफिम विप पर भरोसा करते हैं।

नेटाफिम इरिगेशन (इं) प्राइवेट लिमिटेड  
अर्ज. एम. ओ. 9429230423 फ़ोन अर्ज. एम. ओ. 9429230423  
इरिगेशन | ड्रीप सिस्टम | कॅनॉप ग्रीनहाउस टेक्नोलॉजी  
दुबई, सऊदी, फ़ोन: 9663911 - 9663912, 9663913  
फ़ैक्स: 9663914 - 9663915 / 9663916, 9663917 - 9663918

### मुफ्त बिजली के लिए किसान का हंगामा

नागपुर। कृषि प्रदर्शनी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के भाषण के दौरान ही चंद्रपुर जिले के मांगुरली गांव के किसान काशीनाथ नामदेव बोरेकर ने मुफ्त बिजली की मांग को लेकर हंगामा किया। पहले तो पुलिस प्रशासन ने इसे हल्के में लिया, लेकिन सीएम के भाषण के साथ ही किसान काशीनाथ का पारा भी चढ़ता गया। उसे एक युवक का खुलकर समर्थन मिला और देखते ही देखते वहां उपस्थित किसानों ने काशीनाथ की हां में हां मिलाई। स्थिति को भांप पुलिस जैसे-जैसे करीब पहुंची, आवाज बुलंद होती रही। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने किसान को पकड़ा और बाहर कर दिया।

कृषि प्रदर्शनी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के भाषण के दौरान ही चंद्रपुर जिले के मांगुरली गांव के किसान काशीनाथ नामदेव बोरेकर ने मुफ्त बिजली की मांग को लेकर हंगामा किया। पहले तो पुलिस प्रशासन ने इसे हल्के में लिया, लेकिन सीएम के भाषण के साथ ही किसान काशीनाथ का पारा भी चढ़ता गया। उसे एक युवक का खुलकर समर्थन मिला और देखते ही देखते वहां उपस्थित किसानों ने काशीनाथ की हां में हां मिलाई। स्थिति को भांप पुलिस जैसे-जैसे करीब पहुंची, आवाज बुलंद होती रही। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने किसान को पकड़ा और बाहर कर दिया।

NETAFIM  
KANHAYA CHEMICALS  
300, Sai Sadak, 70/23, Malad Street, East, Mumbai - 400 081, (M.S.), INDIA  
Ph: 2262 0628, 2262 9736  
E-mail: kanhaya@kanhayachemicals.com  
Factory: 15/11, 15/12, C. Industrial Area, Sakinaka, Tal - Pimpri, Dist - Pimpri (M.S.)

### Farm, Farmer and Jain Irrigation... An abiding relationship

Developed Village, Consumer Store, Solar, Progressive Life Style, Information & Technology, Finance, Bank, Food Processing, Participatory Value Addition, Transport, Dairy Business, Agricultural Producer's Federation, Greenhouse, Extension & Training, Bio-Chemical Fertiliser, Village, Agriculture Technique, Harvesting, Drip & Sprinkler Irrigation, Tissue Culture, Veterinary Food, Watershed / Water Harvesting

JAIN  
Jain Irrigation Systems Ltd.  
Srinagar, Jammu, India  
www.jain.com

## संपादकीय

## भारतीय कृषि और चुनौती

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो न केवल इसलिए कि इससे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है बल्कि इसलिए भी भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये एक अजीब विसंगति है कि जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है लेकिन कृषि में विकास की दर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मुकाबले कहीं कम है। पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में विकास दर दो से तीन प्रतिशत के बीच रही है।

वर्ष 2002-03 में कृषि क्षेत्र में विकास दर शून्य से भी कम थी। 2003-04 में इसमें ज़बरदस्त उछाल आया और ये 10 फ़ीसदी हो गई लेकिन 2004-05 में विकास दर फिर लुढ़क गई और ऐसी लुढ़क की 0.7 फ़ीसदी हो गई।

लेकिन सवाल ये उठता है कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों के उलट भारत में कृषि क्षेत्र में विकास की रफ़्तार धीमी क्यों है।

अगर अतीत में थोड़ा झाँककर देखें तो 60 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो बेहतर बीजों, खाद और नई तकनीक की बदौलत पैदावार में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। पैदावार बढ़ी, कृषि में विकास दर बढ़ी और इसका सीधा फ़ायदा किसानों और ग्रामीण लोगों को हुआ। देखते ही देखते भारत के खाद्य भंडार भरने लगे और भारत खाद्यान्नों का निर्यात करने लगा। हरित क्रांति के फ़ायदे भारत को 80 के दशक तक मिलते रहे। फिर 90 के दशक में शुरू हुआ आर्थिक सुधारों का दौर। इनके चलते उद्योगों में तो प्रगति हुई लेकिन कृषि क्षेत्र में एक ठहराव सा आ गया। इस ठहराव के लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जाता है—सिंचाई और ऋण सुविधाओं का अभाव, कृषि में निवेश की कमी, घटिया किस्म के बीज और फसलों में विविधिकरण न होना। समस्या को देखते हुए पिछले कुछ सालों से सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है ताकि ऋण की समस्या से निपटा जा सके। भारत में फसलों की पैदावार तो बढ़ी है लेकिन इनकी गुणवत्ता में कमी के चलते भारतीय फसलों अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी नहीं पिछड़ जाती है। फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है नई तकनीक और उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग जो सस्ते दरों पर उपलब्ध हों। लेकिन ये सब तभी संभव है जब निरंतर शोध का काम होता रहे। तमाम आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत ने लक्ष्य रखा है 10 फ़ीसदी की विकास दर हासिल करने का। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कृषि क्षेत्र में विकास के बगैर ये लक्ष्य हासिल कर पाना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है।

अगर उद्योगों में विकास के साथ-साथ भारत के खेत खलिहान भी हरे भरे हों, तो भारत समुचित और समग्र विकास का दावा कर सकता है—ऐसा विकास जिसका फ़ायदा सिर्फ़ शहरों को ही नहीं गाँवों-कस्बों तक भी पहुँचे।

सुरेश शर्मा  
(प्रधान संपादक)

## सौर ऊर्जा से निकाला...

निकाल देती है। इसके लिए मनुष्यश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर देखी जानी वाली मशीनों में एक बार में दो या तीन गन्ने ही डाले जा सकते हैं, लेकिन इस सोलर मशीन में 8-10 गन्नों को एक साथ डाला जा सकता है।

## चीनी निर्यात पर सब्सिडी

नई दिल्ली, सरकार 40 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात पर 3,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दे सकती है। इससे सरकारी खजाने पर 1,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम का मकसद विदेशों में बिक्री को बढ़ावा देना और नकदी संकट से जूझ रहे उद्योग को प्रोत्साहन देना है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने इस सप्ताह निर्यात सब्सिडी पर दो बार फ़ैसला डाला, क्योंकि कृषि मंत्री शरद पवार 3,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी देने के पक्ष में थे, जबकि खाद्य मंत्रालय ने 2,000 रुपये प्रति टन का प्रस्ताव किया था।

मंत्रालयों के बीच मतभेदों के बीच पवार, वित्त मंत्री पी चिदंबरम और खाद्य मंत्री केवी थामस ने मुद्दे को सुलझाने के लिए आज बैठक की। अंततः 3,500 रुपये प्रति टन सब्सिडी देने पर सहमति बनी, जिसका राकंपा प्रमुख जोरदार वकालत कर रहे थे। खाद्य मंत्री केवी थामस ने बैठक के बाद कहा, 'बैठक में 3,500 रुपये सब्सिडी देने का निगमन किया गया। अब मामला जल्दी ही सीसीईए के पास आएगा।' थामस ने कहा कि 40 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात पर 3,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी से सरकार पर 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

## किसान मित्र राई-सरसों फसल की कटाई, गहाई और भंडारण प्रबंधन



डॉ. अशोक कुमार शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि प्रसार

सरसों अनुसंधान निदेशालय, भारतपुर, राजस्थान

प्रश्न : राई-सरसों फसल की कटाई का लिए उपयुक्त समय क्या है ?

उत्तर : देश के विभिन्न भागों में तोरिया-सरसों एवं राई की फसलें अलग-अलग समयों पर पकती हैं। उत्तरी एवं मध्य भारत में तोरिया अंतर्वर्ती फसल के रूप में उगायी जाती है, जो दिसंबर में पक जाती है, तथा पूर्वी राज्यों (उड़ीसा, असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों) में यह रबी की प्रमुख तिलहनी फसल के रूप में उगायी जाती है और इसकी कटाई फरवरी-मार्च में की जाती है। कश्मीर घाटी में भूरी सरसों मई तक काटी जाती है। प्रमुख राई-सरसों उत्पादक राज्यों जैसे राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फसल फरवरी-मार्च तक काटी जाती है। अगोती अगस्त से सितम्बर अन्त तक बोयी गयी फसल नवंबर-दिसंबर में बोयी गयी फसल की तुलना में पकने में कम समय लेती है। तोरिया की कटाई सामान्यतः 90-95 दिन पर, एवं राई की 130-135 दिन

पर की है। गोभी सरसों की कटाई 155-160 दिन पर एवं करन राई की कटाई 170-175 दिन में की जाती है।

प्रश्न : उपयुक्त समय पर कटाई के क्या लाभ हैं ?

उत्तर : राई-सरसों फसल के कटाई का समय, बोआई की तिथि, उगाई गई किस्म के प्रकार, प्रबंध की कार्य विधियाँ एवं खेती के स्थान पर निर्भर करेगा। उपयुक्त समय पर कटाई करने पर फलियों से बीजों के बिखरने, हरे बीज की समस्या तथा कम तेल अंश युक्त सिकुड़े हुए बीजों के कारण होने वाली हानि कम हो जाती है। बहुत जल्दी कटाई करने पर यदि तत्काल कृत्रिम रूप से सुखाया न जाए तो अधिक पर्णहरित अंश वाले एवं मुक्त वसा अम्लों से युक्त मृत बीजों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी ओर कटाई में देरी करने पर बीजों के छितरा जाने के कारण हानि हो सकती है। फसल को जल्दी तथा देरी से काटने पर 2-4 किंचल पैदावार कम हो जाती है। हरी फली की अवस्था में कटाई करने से तेल की मात्रा में 3-4 प्रतिशत तक कमी हो जाती है।

प्रश्न : राई-सरसों फसल के कटाई की उचित अवस्था क्या है ?

उत्तर : राई-सरसों की फसल की कटाई के लिए सबसे उचित अवस्था तब होती है जब 75 प्रतिशत फलियाँ पीली पड़ जाती हैं और बीज का आर्द्रता अंश लगभग 30-35 प्रतिशत होता है। अधिकांश किस्मों में इस अवस्था के बाद बीज भार एवं तेल अंश में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस

अवस्था पर अंगुलियों के बीच दबाने पर अधिकांश बीज कठोर प्रतीत होते हैं और 30-40 प्रतिशत बीज हरे रंग से अपने प्राकृतिक रंग (भूरे या पीले) में परिवर्तित होना आरंभ कर देते हैं। कच्ची अवस्था पर कटाई करने पर श्वसन क्षतियाँ होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप बीज छोटे रह जाते हैं, तेल अंश में कमी हो जाती है और बीज के



अंकुरण क्षमता में भी काफी कमी हो जाती है। जब 75 प्रतिशत फलियाँ पीली हो जाती हैं तब तेल अंश भी सर्वाधिक होता है।

प्रश्न : राई-सरसों के कटाई के वक्त मौसम कैसा होना चाहिये ?

उत्तर : कटाई ऐसी अवधि में नहीं की जानी चाहिये जब वायु की आपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक हो या वर्षा हो रही हो। वायु की आपेक्षित आर्द्रता बीजों के आर्द्रता अंश को नियंत्रित करती है। सरसों की फसल में बिखराव रोकने के लिए फसल की कटाई सुबह करनी चाहिए क्योंकि रात की ओस से सुबह फलियाँ नम रहती हैं तथा बीज का बिखराव कम होता है।

प्रश्न : राई-सरसों फसल के कटाई, गहाई एवं ओसाई के लिए उपयुक्त तरीका एवं यंत्र क्या है ?

उत्तर : तोरिया-सरसों एवं

राई की कटाई सामान्यतया दर्शती से की जाती है। इन फसलों की कटाई करने के लिए बैल अथवा ट्रैक्टर चालित यांत्रिक हार्वेस्टर या रीपर भी उपलब्ध हैं। भारत में ये यंत्र लोकप्रिय नहीं हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश किसान सीमित साधनों से युक्त, लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं। विकसित देशों में, तोरिया-सरसों एवं राई



फसलों की कटाई के लिए धान्य फसलों के लिए प्रयुक्त हार्वेस्टर कंबाइन का उपयोग किया जाता है। सरसों की फसल की कटाई 30 से 40 सेन्टीमीटर दूँठ छोड़ते हुए करनी चाहिए तथा तोरिया की कटाई 10 से 15 सेन्टीमीटर दूँठ छोड़ कर करनी चाहिए।

परम्परागत तरीकों में अधिकतर फसल की गहाई लकड़ी की डंडी से बीज युक्त फलियों को पीटकर या अच्छी तरह से साफ किये गये खलिहान पर फेलाए हुए सूखे पौधों पर बैलों के पैरों से कुचलकर या ट्रैक्टर चलाकर की जाती है। ओसाई के लिए परम्परागत तरीकों से गहाई किये गये उत्पाद को कंधों की ऊँचाई तक ले जाकर टोकरियों से फर्श पर धीरे-धीरे गिराकर प्राकृतिक वायु धाराओं की सहायता से गहाई किये गये बीजों को भूसी से अलग किया जाता है। परन्तु

इस कार्य हेतु हस्त चलित पंखे या बिजली या ट्रैक्टर चलित पंखों का प्रयोग भी किया जा सकता है। भूसी से अलग किये गये बीजों को छन्नी से छानकर बोरों में भर लिया जाता है।

गहाई हेतु बैल चलित गहाई मशीन या श्रेर का भी उपयोग किया जा सकता है। आजकल बाजार में बहु फसली गहाई यंत्र उपलब्ध है, जिनका तोरिया-सरसों एवं राई की गहाई के लिए बिना किसी जोखिम के उपयोग किया जा सकता है। फसल की गहाई थ्रैसर से करना ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि इससे बीज तथा भूसा अलग-अलग निकल जाते हैं।

प्रश्न : कटाई, गहाई और भंडारण के वक्त राई-सरसों के बीज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए तथा सुरक्षित सरसों बीज के भंडारण के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर : कटाई के समय, बीज में नमी लगभग 30-35 प्रतिशत होनी चाहिए। काटी गयी फसल 5-7 दिन तक धूप में सूखने के बाद बीज की नमी में कमी आती है। सामान्यतया फसल की गहाई उस समय की जानी चाहिए जब बीज की नमी 12-20 प्रतिशत के बीच हो। फसल के बहुत अधिक सूख जाने पर (6-12 प्रतिशत आर्द्रता पर) बीजों के कुचलने एवं क्षति ग्रस्त होने का डर रहता है। सुरक्षित भंडारण के लिए बीजों में नमी 8 प्रतिशत होना चाहिए। गहाई के बाद बीजों को भण्डारण हेतु 8 प्रतिशत

नमी के स्तर पर लाने के लिए धूप में लगभग एक सप्ताह तक सुखायें।

प्रश्न : राई-सरसों के बीज सुरक्षित भंडारण के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

उत्तर : बीज एक जीवित सामग्री है, अतः वे भंडारण के दौरान श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल-वाष्प एवं उष्मा उत्पन्न करते हैं। यदि बीज ठंडे एवं शुष्क होते हैं तो श्वसन की दर घट जाती है। टूटे हुए बीजों की अधिक मात्रा से युक्त नमूनों में साबुत बीजों की अपेक्षा अधिक दर से श्वसन होता हुआ पाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं उष्मा का संचयन सूक्ष्म जीवीय सक्रियताओं को प्रोत्साहित करता है और इसके फलस्वरूप कवक एवं जीवाणु आक्रमण द्वारा बीज का जैविक अपघ्नस बढ़ जाता है। अच्छी भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था करके हानिकारक कीटों से बचा जा सकता है।

भंडारण के दौरान बीज, तेल एवं खली की गुणवत्ता को तापमान तथा आपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। बीजों को भंडार में रखने से पूर्व भंडार को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। भंडारण करने से पूर्व बोरों को 2-3 दिन तक धूप में सूखा लेना चाहिए जिससे उनमें उपस्थित कीट व फफूँदी मर जाए तथा उपस्थित नमी भी कम हो जाए। जहाँ तक संभव हो सके बीजों को नये बोरों में ही भरना चाहिए। जिससे बीज में नमी की मात्रा न बढ़े। बीज भण्डार में बोरों को लकड़ी के तख्तों पर चढ़ा बनाकर रखना चाहिए जिससे देखभाल करने में आसानी रहे। अगर तख्त न हो तो पक्की ईंटों के ऊपर बोरों को चढ़ा बनाकर रखना चाहिए। बोरों को भण्डार की दीवारों से 8-12 इंच दूरी पर रखना चाहिए जिससे बरसात में बीजों में नमी की मात्रा न बढ़े क्योंकि बोरों के दीवारों के पास होने के कारण बीज नमी ग्रहण कर लेते हैं तथा नमी की अधिक मात्रा होने के कारण कभी-कभी बीज भण्डार में ही उग आते हैं तथा बचे बीज भी खराब हो जाते हैं। भण्डारण करने के बाद भण्डार हवा-रोधी कर देना चाहिए जिससे बाहर की हवा अन्दर न आ सके। भंडार की समय-समय पर देखभाल करते रहना चाहिए।

अगर भण्डार में कोई कीट एवं फफूँदी दिखाई पड़े तो तुरन्त कीट एवं फफूँदी नाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। यदि भंडारण के लिए 20 डिग्री सेन्टीग्रेड से नीचे का तापमान तथा 8 प्रतिशत आर्द्रता उपलब्ध रहे तो दो वर्ष तक भण्डारण से भी बीज की गुण व मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी गई है। अगर भंडार की दीवारों में कोई छेद तथा दरार हो तो उसको सीमेंट से बन्द कर देना चाहिए। अगर चूहों के बिल हो तो उनको भी सीमेंट से बन्द कर देना चाहिए।

## सिट्रोनेला घास की अधिक उपज कैसे लें?



आई. एस. यादव, ओ. पी. यादव एवं जे. एस. हुड्डा

औषधीय, संगंध एवम् अल्प प्रयुक्त पौध संभाग अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग सी. सी. एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार - 125 004

इसको गैजनी भी कहा जाता है। इसकी दो प्रजातियाँ हैं—जावा सिट्रोनेला (Cymbopogon winterianus) और सीलोन सिट्रोनेला (Cymbopogon nardus)। जावा सिट्रोनेला के तेल में जिरेनियल (Geranial) की मात्रा अधिक (12-18%) होने के कारण सीलोन सिट्रोनेला की अपेक्षा अधिक उत्तम माना जाता है। अतः जावा सिट्रोनेला की खेती कर्नाटक, आसाम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तरप्रदेश में की जाती है। यह पोयसी, च्वंभंमंमं

कुल की एक तना रहित बहुवर्षीय घास है जिसके पत्तों से तेल आसवित करके निकाला जाता है। जावा सिट्रोनेला घास (सिम्बोपोगोन विन्टेरियानस)

सम्पूर्ण विश्व में लगभग 1800 टन सिट्रोनेला तेल का उत्पादन होता है जिसमें से लगभग 600 टन तेल का उत्पादन भारत में होता है।

उपयोग: साबुन तथा क्रीम निर्माण में सुगंध हेतु आडोमॉस, एंटीसेप्टिक क्रीम एवं अन्य सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्माण हेतु किया जाता है। जलवायु: उष्ण और आर्द्र जलवायु इसके लिए उपयुक्त है। जहाँ 200-250 सें.मी. वर्षा प्रतिवर्ष हो। भूमि: अच्छे पानी के निकास वाली बलुई दोमट तथा दोमट मिट्टी जिसका चम मान 6-7.5 हो।

किस्म: बायो-13, मंजूषा, मंजरी एवं मंदाकिनी (CIMAP, लखनऊ जोर-3-1970 (जोरहट) विकसित किस्में हैं। खेत की तैयारी: खेत भूभ्रूषा/बांरीक तैयार किया हुआ तथा समतल होना चाहिये ताकि पानी ज्यादा समय तक खड़ा न रहे तथा एक समान लगे।

खाद: इसके लिए 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद प्रति एकड़ पर्याप्त है। प्रत्येक कटाई के बाद दो टन प्रति एकड़ गोबर की खाद खेत में मिलायें।

रोपाई की विधि: पुराने स्वस्थ पौधे द्वारा ली गई स्लिप्स को 60ग45 या 60ग60 सें.मी. की



दूरी पर जमीन की उर्वर शक्ति के आधार पर लगायें। रोपाई के तुरन्त बाद पानी लगायें। सिंचाई: पौधे की अच्छी बढ़त एवं पैदावार के लिए काफी नमी की जरूरत होती है अतः वर्षा की उपलब्धता के हिसाब से समय-2 पर पानी लगाए। प्रत्येक कटाई के बाद भी जल्दी ही पानी

लगायें। कटाई लेने से 15 दिन पहले पानी लगाना बन्द कर दें।

निराई व गुड़ाई: आरम्भ में खरपतवार निकालने के लिए 2-3 गुड़ाई जल्दी-जल्दी करें तथा प्रत्येक कटाई के बाद खोदी अवश्य करें।

कटाई: रोपाई के बाद प्रथम कटाई लगभग 4 महीने बाद तथा बाद की कटाईयाँ 2-3 मास के अन्तराल पर ली जानी चाहिये। अनुकूल परिस्थितियों में 4 कटाईयाँ ली जा सकती हैं जबकि सामान्य हालत में 3 कटाई ली जाती है। रोपाई के बाद 4 साल तक अच्छी पैदावार ली जा सकती है। फसल की कटाई जमीन से 15-20 सें. मी. ऊपर से करें।

तेल निकालना: कटाई के बाद कुछ समय धूप लगाकर अन्य संगंध पौधों की तरह आसवन विधि द्वारा संयंत्र से तेल निकाला जा सकता है।

तेल की मात्रा: पहले साल में 2-3 कटाईयाँ में लगभग 40-50 लीटर तेल प्रति एकड़ तथा बाद में 4-5 कटाईयाँ में लगभग 60-70 लीटर प्रति एकड़ प्राप्त किया जा सकता है। तेल का भाव: गुणवत्ता के आधार पर औसतन 300-350 रुपये प्रति लीटर है। सिट्रोनेलाल तेल का मुख्य घटक (32-45%) है। शुद्ध लाभ: प्रथम वर्ष में लगभग 7000-8000 रुपये तथा बाद में 10000-15000 रुपये तक प्रति एकड़ प्राप्त किया जा सकता है।

## अब लुढ़कते प्याज से निकले किसानों के आंसू



**महाराष्ट्र** जब प्याज की कीमतें आसमान छू रही थीं तब बेहतर मुनाफे की आस में महाराष्ट्र के प्याज किसान संतोष ढगे ने अपने खेतों में ज्यादा प्याज की बुआई की थी। लेकिन अब बदले हालात में उनके जैसे हजारों किसानों के समक्ष मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल प्याज की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है जिससे किसानों को मुनाफा तो दूर लागत तक निकलने में पसीने बहाने पड़ रहे हैं। रिकॉर्ड पैदावार के कारण प्याज के भाव उत्पादन लागत से भी नीचे चले गए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान

हो रहा है। किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वर्तमान मौसम में वे प्याज का भंडारण भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से प्याज के सड़े का खतरा है। इसलिए मजबूरी में उन्हें घाटों में प्याज बेचना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक भारी आवक के बीच सुस्त निर्यात के कारण भी प्याज के दाम लगातार गिर रहे हैं। पिछले साल इन दिनों के मुकाबले प्याज आधे भाव पर बिक रहा है। बीते तीन माह के दौरान तो इसका भाव पांच गुना से भी अधिक गिर चुका है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का मॉडल भाव (इस भाव पर 90 फीसदी बिक्री होती है) 735 रुपये, गुजरात की महूआ में 620 रुपये, राजस्थान की जयपुर में 750 रुपये और दिल्ली में 900 रुपये प्रति क्विंटल है। संतोष कहते हैं कि पिछले साल ऊंचे भाव से किसानों ने प्याज की खेती ज्यादा की जिससे उत्पादन भी बंपर हुआ है। ऐसे में किसानों को 600 से 800 रुपये क्विंटल का ही भाव मिल रहा है, जबकि उत्पादन लागत 800-900 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों में जोरदार आवक से प्याज के भाव लगातार इतने गिर चुके हैं कि मुनाफा तो दूर किसानों का खर्चा निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं पिछले साल भाव बेतहाशा बढ़े? पर प्याज निर्यात पर बंदिश से चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 9.87 लाख टन प्याज निर्यात हुआ है, जो पिछली समान अवधि में निर्यात हुए 14.04 लाख टन प्याज से करीब 30 फीसदी कम है।

## चना मजबूत

चने की बिगड़ती हालत को संभालने के लिए सरकारी हाथ बढे? की संभावनाओं को देखते हुए वायदा बाजार में चने के कद्रदान खड़े होने लगे हैं। कमजोर मांग की वजह से चना लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बिक रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार मंडियों में चने की खरीद जल्द शुरू करेगी, जिसका फसला कृषि मंत्रालय में होने वाली सभी राज्यों के कृषि सचिवों की बैठक में लिए जाने की संभावना है। दलहन फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मंत्रालय चने का एमएसपी बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। लेकिन इस साल कभी भी एमएसपी के ऊपर नहीं गई है। पिछले एक साल में चने के दाम करीब 25 फीसदी लुढ़क चुके हैं। चना उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों में सरकारी नीतियों को लेकर नाराजगी है, जिसे सरकार चुनाव से पहले खत्म करना चाहती है। कारोबारियों की मानी जाए तो सरकार इन राज्यों में चने की खरीदारी अगले सप्ताह से शुरू कर सकती है।

## काँयर एक्सपो में 150 करोड़ के निर्यात सौदे

**केरल..** पिछले वित्त वर्ष में 1,166 करोड़ रुपये के काँयर उत्पादों का निर्यात काँयर एक्सपो-2014 बायर-सेलर मीट में काँयर (नारियल के रेशे) से बने उत्पादों को अच्छा रिस्पांस मिला है। इस दौरान 150 करोड़ रुपये के निर्यात सौदे हुए। केरल के आल्पुषा में चल रहे काँयर एक्सपो के चौथे संस्करण में बायर-सेलर मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विदेशी खरीददारों के साथ घरेलू निर्माता कंपनियों ने तकरीबन 150 करोड़ रुपये के सौदे किए। इस बिजनेस मीट का उद्घाटन राज्य के राजस्व एवं काँयर मंत्री अधूर प्रकाश ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य काँयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ उल्लम क्वालिटी के उत्पाद तैयार करना भी है, ताकि विदेशी आयातकों की मांग निरंतर बढ़े, जिससे घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचे।

**Green Mountain**  
Postassium Humate  
Seaweed Extract  
Organic Matter

**US Nitro**  
यु एस नाइट्रो  
Nitrobenzene 22% v/v  
Constant  
Nitrobenzene 22% v/v  
with Natural  
Amino Acid-12%  
Solvent-36%  
Emulsifier-30%

**US Sulphur**  
यु एस सल्फर  
Liquid Sulphur Solution

**US Thio**  
Contents: Thiourea

US Thio, any crop takes a fast growth in minimum time.

**U S Agrochem Pvt. Ltd.**  
Plot No. B-41-42, Neelgiri Colony, Opp. Road No. 9, V.K.I. Area  
Jaipur - 302 039 (Ra.)  
Email: usagrochem\_jaipur@yahoo.com  
Customer Care : 0141-5140277

सबसे सही तरीके किसान, कृषि सबसे अच्छे प्रदान

## नई फसल के गेहूं निर्यात के लिए सौदे शुरू

**घरेलू कारोबार :** दक्षिण भारतीय मिलों ने यूपी से खरीद सौदे किए 1600-1625 रुपये प्रति क्विंटल पर कांडला बंदरगाह पहुंच किए हैं। उत्तर प्रदेश से गेहूं की खरीद 1,440 रुपये प्रति क्विंटल रैक लॉडिंग के आधार पर की गई है। उधर दक्षिण भारत की फ्लोर मिलों ने भी उत्तर प्रदेश से अप्रैल डिलीवरी के करीब तीन रैकों के सौदे किए हैं। एम संस इंटरनेशनल लिमिटेड के सलाहकार टी पी एस नारंग ने बताया कि मई-जून में रूस

और यूक्रेन में गेहूं की आने वाली फसल के आधार पर विश्व बाजार में गेहूं के दाम तब होंगे। हालांकि चालू रबी में गेहूं की घरेलू पैदावार ज्यादा होने का अनुमान है, ऐसे में आगामी दिनों में निर्यात सौदे बढ़े का अनुमान है। केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमएसपी) 260 डॉलर प्रति टन तय किया हुआ है तथा इस समय सार्वजनिक कंपनियों २७५ डॉलर प्रति टन से नीचे की निविदा को स्वीकार नहीं कर रही है। यह सही है कि निर्यातकों के साथ ही स्टॉकिस्टों की अच्छी मांग से गेहूं उत्पादकों को दाम अच्छा मिलेगा। गेहूं के थोक कारोबारी राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,400 रुपये प्रति क्विंटल तय हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारें किसानों को अलग से 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दे सकती है

## रिकॉर्ड पैदावार से निकलेगा आलू का दम

कुछ समय पहले तक सातवे आसमान पर रही आलू की कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को अब इससे राहत मिलने के आसार हैं। पिछले साल आलू की कीमतों में तेजी को देखते हुए किसानों ने इस बार ज्यादा बुआई की है, जिससे उत्पादन बढ़े की उम्मीद है। मौसम भी आलू की फसल के लिए अनुकूल है, जिससे वर्ष 2013-14 के दौरान आलू की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। लिहाजा इस साल आलू के भाव भी नरम रहने की संभावना है। पैदावार बढ़े? की उम्मीद में आलू के भाव अभी से गिरने शुरू हो चुके हैं। जानकारों

का कहना है कि आगे कीमतों में और नरमी के आसार हैं। पिछले साल बुआई के समय आलू महंगा था, जिससे किसानों इसकी बुआई ज्यादा की। इसके अलावा मौसम भी अनुकूल रहने से वर्ष 2013-14 के दौरान देश में रिकॉर्ड 464.43 लाख टन आलू के उत्पादन का अनुमान है जबकि वर्ष 2012-13 में 453.43 लाख टन आलू पैदा हुआ था। जानकारों का कहना है कि आलू के उत्पादन में सबसे ज्यादा २४ फीसदी बढ़ोतरी ओडिशा में होने का अनुमान है। महाराष्ट्र में 20 फीसदी, हरियाणा में 9 फीसदी, कर्नाटक व मध्य प्रदेश में 5 फीसदी और मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 4 फीसदी पैदावार बढ़े का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के आलू किसान बटुकनारायण मिश्रा भी मानते हैं कि बेहतर भाव मिलने से किसानों ने ज्यादा आलू लगाया है। आजदपुर मंडी के आलू कारोबारी त्रिलोकचंद शर्मा ने कहा कि अच्छी पैदावार की उम्मीद से इस साल आलू के

## केरल सरकार करेगी रबर की खरीद

**केरल** सरकार खुले बाजार में रबर की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उत्पादकों से इसकी खरीद करेगी। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री उम्मेन चांडी ने आज राज्य विधानसभा में की। रबर की कीमतों में लगातार गिरावट के मसले पर विपक्षी सदस्य के सुरेश कुरुप द्वारा रखे गए एक प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से इसके लिए वित्तीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय से भी रबर खरीदने का आग्रह किया है, ताकि कीमतों में स्थिरता आ सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है। खरीद से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार की तर्ज पर रबर की स्थानीय कीमतों में भी गिरावट का रूझन

बना हुआ है। लेकिन फिर भी केरल में रबर के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा हैं। सुरेश कुरुप ने आरोप लगाया कि शुल्क मुक्त रास्तों से आयात और कम शुल्क पर आयात की वजह से बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इस मसले पर कोई कदम नहीं उठा रही है।

**नई दिल्ली,** भारत से मसालों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में

मात्रा के लिहाज से 28 फीसदी, रुपये में कीमत के लिहाज से 46 फीसदी और डॉलर में 32 फीसदी बढ़ा है। वर्ष 2013 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मसालों के निर्यात की कीमत 8377.20 करोड़ रुपये (1,39.65 करोड़ डॉलर) और मात्रा 5,08,555 टन

## बढ़िया बर्फबारी से बढ़ेगी सेब की लाली

**जम्मू-कश्मीर** महंगाई के इस दौर में सेब आपकी जेब को थोड़ी राहत दे सकता है। बेहतर पैदावार से इस बार सेब की कीमतें कम रह सकती हैं। सेब उत्पादक क्षेत्रों में इस बार अच्छी बर्फबारी होने सेब को फायदा पहुंच रहा है, जिससे सेब की पैदावार बढ़ेगी की संभावना है। मुख्य सेब उत्पादक राज्य जम्मू-कश्मीर में इस बार पिछले साल से भी ज्यादा बर्फबारी हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के कुछ सेब उत्पादक इलाकों में पिछले साल से कम बर्फ पड़ी है। लेकिन सेब किसानों का कहना है कि मौसम सेब के अनुकूल है। पिछले साल कश्मीर में 12 करोड़ पेटेटी और हिमाचल में ३ करोड़ पेटेटी (प्रति पेटेटी 18 से 20 किलोग्राम) सेब हुआ था। इन दोनों राज्यों के अलावा उत्तराखंड में भी सेब का उत्पादन होता है। पिछले साल त्रासदी के कारण उत्तराखंड में सेब की लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई थी लेकिन इस बार कुछ सुधार हो सकता है।



## गेहूं में बिकवाली से कमा सकते हैं मुनाफा

**नई दिल्ली...** बुवाई क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी के साथ अनुकूल मौसम से चालू रबी में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। गेहूं की बुवाई चालू रबी में 5.7 फीसदी बढ़कर 315.32 लाख हेक्टर में हुई है। मार्च-अप्रैल महीने में उत्पादक मंडियों में गेहूं की नई फसल की आवक शुरू हो जायेगी। हालांकि निवेशकों की खरीद से एनसीडीईएक्स पर मार्च महीने के गेहूं के वायदा अनुबंध में पिछले पांच दिनों में २ फीसदी की तेजी हो आई है लेकिन बंपर उत्पादन को देखते हुए मार्च में गेहूं की मौजूदा कीमतों में 10 से 12 फीसदी की गिरावट आने की संभावना है। एनसीडीईएक्स पर मार्च महीने के गेहूं के वायदा अनुबंध में पिछले पांच दिनों में २ फीसदी की तेजी आकर शुक्रवार को भाव 1,612 रुपये प्रति क्विंटल हो गए जबकि 3 फरवरी को मार्च महीने के वायदा अनुबंध में इसके भाव 1,579 रुपये प्रति क्विंटल थे। एग्री विशेषक अभय लाखवान ने बताया कि चालू रबी में गेहूं के बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही अभी तक मौसम भी फसल के अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में आगामी दिनों में नई फसल की आवक बनने के बाद गेहूं की मौजूदा कीमतों में गिरावट की ही संभावना है। इसलिए निवेशक मौजूदा कीमतों पर बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं। श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट कंपनी के प्रबंधक संदीप बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2014-15 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है जबकि खुले बाजार में गेहूं का स्टॉक नहीं होने के कारण रोलर फ्लोर मिलें गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से ही कर रही हैं। मार्च महीने में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए गेहूं की आवक शुरू हो जायेगी, जबकि अप्रैल में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नई फसल की आवक बनेगी।

**MANUFACTURER AND BULK SUPPLIER OF FERTILIZERS PRODUCTS**

**UDIT OVERSEAS PVT. LTD.**

137, INDUSTRIAL AREA DEHRA, TEHSIL-CHOMU, DISTT. JAIPUR

**Products Range:-**

- Micronutrients
- Bio Insecticide
- Mixture
- Bactericide
- Secondary Nutrients
- Wetting Agent
- Growth Promoters
- Zyme
- Bio Stimulants
- Tonic
- Bio Fungicide

**WE WELCOME YOUR INQUIRY**

**CONTACT DETAIL**

**MR. ALOK BENIWAL**

**MOB: 9660258447**

## २८ फीसदी इजाफा

लिहाज से 129 फीसदी और कीमत के लिहाज से ६२ फीसदी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की इसी अवधि में इनका निर्यात 6,916 टन रहा था, जिससे 1,223 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। इनसे होने वाली आमदनी मिर्च से थोड़ी ही कम रही। अप्रैल से नवंबर, २०१२ के दौरान मिर्च से सबसे ज्यादा आय हुई थी। मसाला बोर्ड ने कहा कि इस साल 1,81,500 टन मिर्च का निर्यात हुआ, जिससे 1,614.17 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। वहीं, पिछले साल मिर्च का निर्यात 1,74,798 टन रहा था, जिसकी कीमत 1,408.68 करोड़ रुपये थी।

# भारतीय कृषि बीमा की वर्तमान स्थिति

विनोद कुमार वर्मा, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. गजानन्द जाटव डॉ. धर्मपाल सिंह

1. विनोद कुमार वर्मा, शोध छात्र, विद्यावाचस्पति, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (राज.)  
2. डॉ. प्रदीप कुमार, सहायक आचार्य, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (राज.)

3. डॉ. गजानन्द जाटव, सहायक आचार्य, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर

4. डॉ. धर्मपाल सिंह सहायक आचार्य, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर

भारत में कृषि मानसून एक जुआ है। स्वतंत्र भारत में कृषि विकास एवं अनुसंधान की लम्बी यात्रा के बाद भी आज अनाज (गेहूँ 10.5, चावल 44, ज्वार 91, बाजरा 91.1 तथा मक्का 79.9) उत्पादन का 47.7 प्रतिशत, तिलहन 72 प्रतिशत, कपास 63.9 प्रतिशत तथा दालों के 85 प्रतिशत कृषि क्षेत्र का पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। इस तथ्य की पुष्टि करता है। भारी वर्षा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूकम्प, कीट एवं बीमारियों के आक्रमण जैसी प्राकृतिक आपदाएँ कोढ़ में खाज जैसी की स्थिति पैदा करती है। जलवायु अस्थिरता, तापमान में वृद्धि, अनिश्चित मानसून तथा ग्लोबल गांव की बाजार नियंत्रित स्थितियों एवं परिस्थितियों ने खेती एवं पशुधन विकास को कहीं अधिक जोखिम पूर्ण एवं हानि के प्रति संवेदनशील बना दिया है। यही कारण है कि देश के 12.73 करोड़ काश्तकारों, जिनमें लगभग 82 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान हैं तथा 10.68 करोड़ कृषि श्रमिकों के साथ साथ 48.5 करोड़ पशुसंपदा के ऊपर हमेशा संकटों के बादल छाए रहते हैं। इसी के चलते कृषि बीमा की अवधारणा अस्तित्व में आई। वस्तुतः कृषि बीमा (फसल, पशुपालन, बागवानी इत्यादि कृषि उत्पादन जोखिमों से किसानों को हुए नुकसान को, समान जोखिम के विरुद्ध अन्य छोटे छोटे योगदान कर्ता किसानों से प्रीमियम के रूप में एकत्रित संचित निधि से हल्का अथवा कम किया जाता है। परन्तु, कृषि बीमा अवधारणा के व्यापक एवं दूरगामी उद्देश्यों में प्राकृतिक आपदाओं से जनित फसल एवं पशुधन हानि के जोखिमों से किसानों को सुरक्षित करना, आर्थिक स्थिति में स्थायित्व तथा आय में निरंतरता बनाए रखना शामिल है जिससे किसान नवीन कृषि प्रौद्योगिकी में अधिक लागत लगाने का जोखिम उठाने में समर्थ हो सकें। बैंकों की ऋण वसूली जोखिम को कम किया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं किसानों को महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका को स्वीकारते हुए स्वतंत्र भारत की नीति समय समय पर इस दिशा में कदम उठाते रहे हैं। इसके बावजूद 21 वीं सदी में भी कृषि एवं किसान संकट में हैं। जबकि कृषि विशेषज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास की योजनाएँ बहुत सोच विचार के बाद सही ढंग से बनाई गई हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि योनजाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिक संसाधन नहीं हैं, तो इतने अपर्याप्त भी नहीं रहे हैं। प्रश्न उठता है तो फिर कमी कहाँ रही है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर दूढ़ने के लिए भारत में कृषि बीमा की प्रगति एवं उसके परिणामों पर एक नजर डालना अनिवार्य हो जाता है।

## भारत में कृषि बीमा की प्रगति

प्रयोगों के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए सर्व प्रथम वर्ष 1972-73 में साधारण बीमा निगम ने व्यक्तिगत निवेदन/दृष्टिकोण के आधार पर कपास की एच-4 प्रजाति के लिए फसल के बीमा हेतु प्रायोगिक योजना शुरू की। बाद में इसे अन्य फसलों पर लागू किया गया। वर्ष 1978-79 तक यह योजना लागू रही। इस योजना का लाभ मात्र 3110 किसानों तक ही सीमित रहा। बाद में प्रो.वी.

एम. दांडेकर की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1979 में भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा राज्यों की सहायता से प्रायोगिक फसल बीमा योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर 13 राज्यों में लागू की, जिसमें शत प्रतिशत ऋण की सीमा को कवर किया गया। वर्ष 1984-85 तक इस योजना से 6.27 लाख किसानों की फसल का बीमा किया गया। व्यावहारिकता के अभाव में यह योजना भी सफल नहीं हो पाई। इस अवधि को भारतीय कृषि बीमा के इतिहास में प्रथम चरण के रूप में परिभाषित किया जाता है।

किसानों की खेती में अन्तर्निहित जोखिमों एवं चुनौतियों तथा पिछले अनुभवों के आधार पर

दूसरे चरण में अप्रैल 01, 1985 से भारत सरकार ने संशोधित व्यापक फसल बीमा योजना राज्यों की स्वीच्छिक सक्रिय सहभागिता के आधार पर शुरू करने का फैसला किया। जिसमें 15 राज्य तथा 2 संघशासित क्षेत्र शामिल हुए। इस योजना में बीमाकित राशि की मात्रा बैंकों से प्राप्त ऋण के बराबर निर्धारित की गई। जिसे बाद में 150 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। खरीफ 1999 तक इस योजना का घोषित लाभ देश के 7.63 करोड़ किसानों ने उठाया, जिन्हें क्षतिपूर्ति दावे के रूप में 2303.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जिसका दावा अनुपात 1:5.71 था। इस योजना का चिंतानक पक्ष यह रहा कि दावा भुगतान एवं बीमाकित किसानों की संख्या में राज्यों की समान हिस्सेदारी नहीं रही। दावों के भुगतान का 85 प्रतिशत हिस्सा देश के चार राज्यों, गुजरात 47 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश 21 प्रतिशत, महाराष्ट्र

9 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत ओडीशा के किसानों को दिया गया। सबसे अधिक कपास एवं मूंगफली उत्पादक किसानों ने ही इस योजना में रुचि दिखाई। शेष फसलों का बीमा सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में ही रहा। नीतिगत, प्रशासनिक एवं व्यावहारिक अदृष्टता के चलते योजना किसानों के मध्य व्यापक लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई और अधिकांश किसान योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गये। योजना के क्रियान्वयन के स्तर पर सामने आई व्यावहारिक कठिनाईयों, किसानों की आय में निरंतर गिरावट, उत्पादन एवं उत्पादकता में आई स्थिरता तथा देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों की आत्महत्याओं की दर्दनाक खबरों ने नीति निर्माताओं को फसल बीमा योजनाओं को नए पूर्वनिर्धारण करने पर मजबूर कर दिया। अतः वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से भारतीय साधारण बीमा के समन्वय से राष्ट्र कृषि बीमा योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें सभी खाद्य फसलों, तिलहन, बागवानी फसलों को शामिल किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गन्ना,

प्याज, आलू, हल्दी, मिर्च, तिलहन, जूट, धनिया, जीरा, लहसुन इत्यादि को रखा गया। इसी समय आधुनिक बीज उद्योग को बढ़ावा देने, बीज उत्पादकों की आय में स्थायित्व तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना भी शुरू की गई। दुर्भाग्यवश पूर्व की तरह ये तीसरे चरण की योजनाएँ भी लक्ष्य भेदने में असफल रही।

आखिर भारतीय साधारण बीमा निगम (35), नाबार्ड (30), नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लि., न्यू इण्डिया इश्योरेंस कं. लि., ओरियन्टल बीमा कं. लि., एवं यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कं. लि. प्रत्येक ने 8.75 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ मिलकर 150 करोड़ रुपये को अधिकृत शेयर पूंजी तथा 200 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी से एग्रीकल्चरल इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. नाम की बीमा संस्था को दिसम्बर 20, 2002 में निर्गमित कराया, जिसने अप्रैल 01, 2003 से भारतीय साधारण बीमा निगम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन का कार्य अपने हाथ में ले लिया था। आज कृषि बीमा कम्पनी ऑफ इण्डिया लि. कृषि में जोखिमों से सुरक्षा के निमित्त तमाम कृषि बीमा उत्पाद किसानों के मध्य ला रही है जिसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना, वर्षा, सूखा सुरक्षा कवच, कृषि आय योजनाएँ शामिल हैं। इसके बाद भी कृषि एवं किसानों की स्थिति खराब होती जा रही है। विश्व में सबसे अधिक किसानों को बीमा उपलब्ध कराने वाली भारत की कृषि बीमा कं. लि. ने अभी तक पशुधन बीमा योजना को अपने हाथ में नहीं लिया है। खेती एवं पशुपालन का चोली दामन का साथ है। जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न अभिकरणों की परस्पर व्याप्ति जहाँ किसानों को भ्रमित कर रही है वहीं इसके क्रियान्वयन एवं समन्वय में व्यावहारिक कठिनाईयों किसानों को इसे अपनाने से रोक रही है। वर्ष 2013 के दौरान 24115442 किसानों और 56907029 हैं। भूमि को आच्छादित कर ए.आई.सी. विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा कम्पनी बन गई है। इस वर्ष तक 540 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया।

वर्ष 2012-13 तक कंपनी के पास मात्र 209 कर्मचारी व अधिकारी हैं। जिनके हाथ में देश के 12.73 करोड़ कृषि जोतों की सुरक्षा एवं सहायता का जिम्मा है। स्थापना के 6 वर्ष बाद भी कंपनी के पास विषय विशेषज्ञों एवं कॉन्डर आधारित स्टाफ एवं प्रबंधन तंत्र का ग्राम स्तर से लेकर जिला व राज्य स्तर तक अभाव कृषि बीमा योजनाओं को अपना रहे हैं। इसमें कर्ज न लेने वाले स्वीच्छिक किसानों की संख्या नाम मात्र ही है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि अभी तक सभी कृषि बीमा योजनाएँ न केवल किसानों का विश्वास जीतने में असफल रही हैं बल्कि राज्यों में कृषि बीमा का लाभ उठाने में असमानता आज भी बनी हुई है। रबी मौसम 2012-2013 में महाराष्ट्र 17.58, उड़ीसा 4.96, आन्ध्र प्रदेश 12.62 तथा मध्य प्रदेश 8.92 कृषि बीमा का लाभ उठाने में अग्रणी राज्य

रहे हैं।

## समस्या की पृष्ठभूमि

भारतीय किसानों की असली समस्या उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य की है। राष्ट्रीय किसान आयोग की अंतिम रिपोर्ट के एक अध्ययन के अनुसार भारत के प्रमुख बारह धान उत्पादक राज्यों में से सिर्फ चार राज्यों में ही धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से अधिक था। शेष आठ राज्यों में धान की उत्पादन लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक थी गेहूँ की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा थी। जहाँ तक दुग्ध उत्पादन व्यवसाय का प्रश्न है, तो सच यह है कि भारत में दूध की कीमत इण्डिया के किसी ब्रांडधारी पानी की कीमत से कहीं कम है। प्रश्न उठाना स्वभाविक है कि आखिर किसान को घाटे का बीमा कराने से लाभ क्या है। बीमा तो संभावित क्षति

से सुरक्षा हेतु कराया जाता है। भारतीय किसान तो घाटे का बीमा कराने के लिए पहले से ही अभिशप्त है। इस स्थिति में कृषि बीमा का लाभ किसानों को मिलना कैसे सुनिश्चित माना जा सकता है आपदा की स्थिति में ऋण धारक किसान को क्षति पूर्ति के रूप में प्राप्त राशि उसके ऋण खाते में चली जाती है। फिर बीमा की दावा राशि से किसान द्वारा लिए ऋण पूर्ति असंभव है। भारत के 48.6 प्रतिशत कृषि परिवार आज भी ऋणग्रस्तता में फंसे हुए हैं जबकि सीमान्त किसानों के 61 प्रतिशत परिवारों पर ऋणग्रस्तता का भार है।

यह विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उपयुक्त आंकड़ों में ऑफ मौसम की समाप्ति के बाद (दिसम्बर से मार्च) जिसे गांवों में अन्न संकट अवधि के रूप में जाना जाता है। वस्तु के रूप में उधार लिए गए खाद्यान्न जो तीन महीने बाद लगभग सवा गुना करके चुकाना पड़ता है शामिल नहीं है। इस तरह गरीबी की गलत अवधारणा तथा अन्न स्थिर कृषि उत्पादन व उत्पादकता की स्थिति में कोई भी आधुनिक कृषि तकनीक एवं कृषि बीमा योजना किसानों के लिए स्वयं अपना अर्थ खो देती है। वास्तविक अर्थों में बीमा फसल का नहीं ऋण वसूली का होता है इसलिए बीमा

प्रीमियम को ऋण लागत के रूप में परिभाषित करना उचित होगा जो फसल के उत्पादन लागत का हिस्सा है, जिसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय शामिल नहीं करता है। दरअसल बीमा की अवधारण विकसित देशों से आयातित है, जहाँ हर स्तर पर बीमा के द्वारा आर्थिक जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा एवं सहायता प्रदान की जाती है जहाँ लोग आय का नहीं विलासिता का बीमा कराते हैं जहाँ आय समस्या नहीं है। भारत के संबंध में स्थिति एक दम उलटी है। यहाँ बीमा फसल का नहीं गरीबी एवं घाटे का किया जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्ययन से स्पष्ट है। इस स्थिति में बीमाकित तथा बीमा कंपनी दोनों ही घाटे में रहती है। यही कारण है कि अभी तक कोई भी निजी बीमा कंपनी कृषि बीमा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से उतरने को तैयार नहीं है। कृषि तथा कृषि के अर्थशास्त्र का कड़वा सच यह है जिसकी व्यवहारिकता को कृषि बीमा तथा इससे संबंधित नीतियों को बनाते समय अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है जबकि इस सच्चाई को केन्द्र में रखकर कृषि एवं ग्रामीण विकास की नीतियाँ तथा कृषि बीमा की योजनाएँ नहीं बनाई जाती हैं। तब तक किसानों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा।

## व्यावहारिक चुनौतियाँ एवं समाधान

फसल नष्ट होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का निर्धारण पहले से तैयार फार्मूले के अनुसार किया जाता है। क्षतिपूर्ति का आकलन तभी संभव होता है जब कम पंचायत स्तर पर फसल में नुकसान हुआ हो। व्यक्तिगत चार-छः किसानों को फसल नष्ट होने की स्थिति में नहीं। जबकि बीमा प्रीमियम किसान व्यक्तिगतरूप से भरता है। ऐसे में फसल को कैसे बीमित माना जा सकता है इस तरह क्षतिपूर्ति का यह फार्मूला ही गलत एवं अव्यावहारिक है। फसल उत्पादन में बुवाई से लेकर अंतिम उत्पाद के बाजार में पहुँचने तथा मूल्य हाथ में आने तक हर स्तर पर भारी जोखिम शामिल होता है जबकि कंपनियाँ सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए बीमा प्रदान करती हैं। बाजार जनित एवं कटाई के बाद उत्पन्न जोखिम शामिल नहीं होते हैं। आज भी बीमा कंपनी द्वारा फसल के लिए उनके द्वारा निर्धारित वित्तीय मान के बराबर ही अतिरिक्त फसल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यदि किसान इससे अधिक का बीमा कराना चाहता है, तो उसे बढ़ी हुई प्रीमियम दरे देनी होती है।

कृषि बीमा कं. लि. का गठन हुए दस वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी कृषि जोखिम से सुरक्षा के निमित्त उसके पास कृषि बीमा उत्पादों के निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन एवं शोध हेतु कृषि विशेषज्ञों, मानव संसाधन का नितान्त अभाव है बीमा उत्पादों के त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कंपनी में हर स्तर पर केंद्र आधारित विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति अनिवार्य है। आर्थिक हालातों एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मदेनजर इनकी सेवा शर्तों में अनिवार्य रूप से गांवों में रहने, क्षेत्रीय विकास, कृषि उत्पादन, उत्पादकता, पशुधन विकास, गरीबों के लिए रोजगार सृजन इत्यादि की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से शामिल की जानी चाहिए। ये गांवों में ग्रामीणों के मध्य आसानी से एक मित्र दार्शनिक, दिशा निर्देशक तथा कृषि विशेषज्ञ की भूमिका प्रभावी ढंग से निभाते हुए किसानों को छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में भी मददगार साबित होंगे। इससे किसानों के अन्दर कृषि बीमा योजना के प्रति न केवल विश्वास पैदा होगा बल्कि इसे अपनाने की दिशा में आगे आएंगे। एक तरफ बीमा उत्पाद को व्यक्तिगत स्तर पर लागू करना संभव होगा, तो दूसरी तरफ फसल ऋण के सही व पूरे उपयोग की संभवनाएँ बढ़ेगी जिसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादकता एवं उत्पादन पर पड़ेगा। यह तभी संभव होगा जब बीमा उत्पाद की सफलता असफलता, कार्यकुशलता, लाभप्रदता एवं योजना के अन्तिम परिणामों की

निष्पादकता की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जवाबदेही इस केंद्र आधारित स्टाफ की निर्धारित की जाएगी। ऐसा करना वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की भावना के अनुरूप होगा। इसके लिए देश में पर्याप्त संख्या में कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर मौजूद हैं, जिन्हें गांवों में रहने में कोई परहेज नहीं होगा।

अतः जरूरी है कि भारतीय कृषि बीमा कं.लि. का स्वरूप बहुआयामी एवं संयुक्त उत्पादोन्मुख कृषि एवं ग्रामीण बीमा प्रणाली का हो। यह साधारण बीमा निगम की मनी बैंक पॉलिसी जैसे संयुक्त कृषि बीमा उत्पाद के विकास की आवश्यकता है, जो कृषि एवं पशुपालन दोनों को अपने दायरे में ले सके, जिसकी परिपक्वता अवधि के बाद जोखिम कवर करने के साथ साथ पैसा मिलने की संभावना बनी रहे। जितनी जल्दी हो कृषि बीमा कंपनी गांव पंचायत ब्लॉक तहसील जिला मंडल राज्य स्तर पर अर्ध संरचनात्मक ढांचा विकसित करने की दिशा में तुरंत कदम उठाए। वर्तमान में कृषि बीमा व्यवस्था में स्थानीय राजस्व विभाग, कृषि विभाग, मौसम विभाग, सांख्यिकी विभाग, बैंक, राज्य व केन्द्र सरकार तथा बीमा कंपनी इत्यादि शामिल हैं। इस स्थिति में किसानों को कृषि बीमा कहां से कराया तथा भुगतानों के दावे हेतु किसके पास जाएं। संस्थाओं की बहुलता प्रक्रिया के कारण इनमें समन्वय, जिम्मेदारी, जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता का नितान्त अभाव है। अतः सबसे महत्वपूर्ण बीमा व्यवस्था में शामिल विभिन्न एजेंसियों को कम करके मात्र एक या दो संस्थाएँ इस काम को पूरी तरह से अपने हाथ में ले। कृषि बीमा शिक्षा के प्रचार प्रसार का सघन अभियान शुरू करें। क्षतिपूर्ति आकलन के फार्मूले को संशोधित कर व्यावहारिक बनाने की दिशा में कोई ठोस व निर्णायक कदम उठावें। जिसमें किसान बीमा उत्पादों को स्वीकार कर सके, क्षति होने की स्थिति में उन्हें उसका लाभ मिल सके।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका

95 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 10,563 शाखाएँ भारत के गांव गांव में फैली हुई हैं। अतः ग्रामीण कृषि बीमा मॉडल के आधार पर केंद्र आधारित स्टाफ के साथ कृषि एवं ग्रामीण बीमा की जिम्मेदारी कुछ सुधारों एवं संशोधित सेवा शर्तों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंपी जा सकती है बशर्त कि ये बैंक पहले से ही कृषि बीमा प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

## कृषि बीमा उत्पादों की परस्पर व्याप्ति

सबसे महत्वपूर्ण कृषि बीमा उत्पादों की बहुलता एवं परस्पर व्याप्ति ने किसानों एवं मजदूरों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। उत्पादों की बहुलता ने योजना के अन्तिम परिणामों को न केवल प्रभावित किया है बल्कि इसे एकदम अव्यावहारिक बना दिया है जहाँ दो जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया, वहाँ गरीब, सीमान्त व लघु किसान कितने बीमा कराएगा। आय का, फसल का, पशु का, वर्षा का या फिर अपनी जिंदगी का। निश्चय एवं व्यस्त किसानों के लिए इतने बीमा उत्पादों की प्रक्रियागत जटिलता प्रीमियम भुगतान रख रखाव तथा भागदौड़ का विचार ही बीमा की ओर देखने से रोक देता है। अतः किसानों को एक ऐसी व्यापक, सरल व समन्वित कृषि बीमा उत्पाद की जरूरत है जिसमें उपयुक्त सभी जोखिम शामिल हों। इसके लिए पैकेज बीमा की दिशा में आगे बढ़ना होगा जिससे योजनाओं के दोहराव से बचा जा सके और किसान आसानी से इन्हे स्वीकार कर सके।

भारतीय रिजर्व बैंक एवं कृषि बैंकिंग महाविद्यालय की निर्णायक भूमिका

कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित शोध, योजना एवं नीतियों का गहराई से अध्ययन करने हेतु रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त व उत्कृष्ट अर्ध संरचना है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाएँ इस दिशा में सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं। इसे और कृषि उन्मुख एवं विशिष्ट बनाने के लिए रिजर्व बैंक अपने वर्तमान स्टाफ से कृषि क्षेत्र के स्नातकों, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट कर्मचारियों को मिला कर प्राथमिक डाटा पर आवश्यकता आधारित शोध तथा अन्य कृषि नीतियों के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में एक नए विभाग को स्थापना कर सकता है, इसे रिजर्व बैंक के उपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। मात्र एक परिपत्र से एक कॉन्डर आधारित मानव संसाधन के साथ एक नये विभाग का गठन करके कृषि क्षेत्र में जमीनी स्तर पर और गुणवत्तापूर्ण एवं यथार्थ पूरक अध्ययन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को सुदृढ़ किया जा सकता है। अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय किसानों को ऐसी एक सरल, योजना की जरूरत है जो आसानी से उनके दरवाजे पर उपलब्ध व्यापक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बीमा पैकेज दे सके। जो न केवल प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उसे वित्तीय सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करे बल्कि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ टिकाऊ कृषि आय का आधार बन सके। क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान तुरन्त व समय पर प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण बीमा का भी कार्य अपने हाथ में ले सके। यह तभी संभव है जब कृषि बीमा नीतियों के क्रियान्वयन एवं उनके अन्तिम परिणामों को निष्पादन हेतु शामिल कर्मचारियों एवं संस्थाओं की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही क्रियान्वयन के हर स्तर दृढ़ता पूर्वक किया जाए।

## संदर्भ स्रोतः-

1. आर्थिक समीक्षा 2012-13 वित्त मंत्रालय भारत सरकार
2. कृषि बीमा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2012-13
3. कृषि बीमा कम्पनी ली. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना व्यवसाय सांख्यिकी 2012-13
4. भारत में फसल बीमा का इतिहास, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया ली. आर्थिक समीक्षा वर्ष 2001 से 2012.
- 13 वित्त मंत्रालय भारत सरकार





## मंथन महिला सशक्तिकरण



महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी। सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती हैं और कभी-कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे धकेलती हैं।

प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्या हो सकती है? इसका जवाब बहुत ही सरल, पर लक्ष्य कठिन है। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी पिछले 10-15 वर्षों में शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। सामान्य तौर पर ऐसा देखने में आया है कि पुरुष पंचायत प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य पर जोर दिया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। शुरुआती दौर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कठपुतली की तरह पुरुषों के इशारे एवं दबाव में उनकी मर्जी के खिलाफ अलग कार्य नहीं किया। आज भी अधिकांश जगहों पर महिला पंच-सरपंच मुखर तो हुई हैं पर सामाजिक मुद्दों के प्रति उनमें अभी भी उदासीनता है। इसके बावजूद महिला पंचों एवं सरपंचों से ही सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है क्योंकि सामाजिक सशक्तिकरण के लिहाज से यह उनके लिए भी जरूरी है।

हालाँकि महिला सशक्तिकरण के अनेक अन्य आयाम भी हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा रोजगार में आनेवाली समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। हालाँकि केवल कानून और सरकारी विनियमों से ही इन सामाजिक कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। हमें समुचित जन-शिक्षा द्वारा समर्थन प्राप्त कर सुदृढ़ एवं अनवरत सामाजिक स्तर पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

ऋतु कपिल  
(कार्यकारी संपादक)

# भिण्डी की उन्नत खेती

डॉ. राकेश कुमार शर्मा -विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यानिकी)

डॉ. स्वप्निल दुबे प्रभारी कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायसेन

भिण्डी एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, इसके फलों को पौधों से हरी, कच्ची एवं नर्म अवस्था में ही तोड़कर सब्जी के रूप में उपयोग लिया जाता है। भिण्डी गर्मी व वर्षा के मौसम की प्रमुख फसल है। गर्मी के मौसम में जब अन्य सब्जियों की कमी रहती है तब सब्जी आपूर्ति में भिण्डी का अच्छा योगदान रहता है तथा इन दिनों भिण्डी की कीमत भी अच्छी रहने से मुनाफा भी अच्छा मिल जाता है। किसान भिण्डी की अग्रेती बुवाई फरवरी माह में करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके जड़ व तनों के रस को चीनी उद्योग में गन्ने के रस को साफ करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। आयुर्वेद में इसे यकृत में पथरी की बीमारी में फायदेमंद बताया गया है।

**जलवायु:** भिण्डी गर्मी एवं खरीफ की प्रमुख सब्जी फसल है। बीज के अंकुरण के लिए 17-22 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है तथा बढ़वार के लिए ३५ डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। जब दिन का तापमान ४२ डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक हो जाता है तो फूल गिर जाते हैं या परागण की क्रिया नहीं होने से फलों में दाने नहीं बनते हैं।

**भूमि:** भिण्डी की खेती के लिये दोमट व बलुई दोमट मिट्टी जिसका पी. एच. मान 6.0 - 6.8 हो तथा जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो, उपयुक्त रहती है। सिंचाई की सुविधा तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

**उन्नत किस्में:**

१. पूसा सावनी- इसके फल 10-15 से.मी. लम्बे, पतले, चिकने, गहरे हरे, पांच धारियों वाले होते हैं। वर्षा काल की अपेक्षा बसन्त में इनके पौधे से छोटे फल आते हैं।

2. पूसा ए-4 - पीतशिरा मोजेक के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। फल गहरे हरे, 12-15 से.मी लम्बे तथा पहली तुड़ाई 45 दिन बाद होती है।

3. अकी अनामिका - यह एक पीत शिरा मोजेक रोग प्रतिरोधी किस्म है। पौधे लम्बे, पाखाओं वाले, फल लम्बे, तथा गहरे हरे रंग के होते हैं। बुवाई के 45-5० दिन में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं।

४. वी.आर.ओ-६ - इसे काशी प्रगति के नाम से भी जाना जाता है। पित शिरा विषाणु रोग से अवरोधी प्रजाति है पौधे की लम्बाई गर्मी में 130 से.मी. तथा बरसात में 175 से.मी. होती है तथा गांठे भी नजदीक होती हैं। गर्मी में पैदावार 135 क्विंटल है। तथा बरसात में 190 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है।

५. वी.आर.ओ-10 - इसे काशी सातधारी के नाम से जाना जाता है। इसमें फूल 42 दिन में आ जाते हैं। यह प्रजाति पित शिरा मोजेक व प्रारम्भिक पत्ती मरोड़ विषाणु से पूर्णतया मुक्त है। इसकी पैदावार बरसात में 140 क्विंटल/हे. से भी ज्यादा ली जा सकती है।

6. वर्षा उपहार - पौधे मध्यम ऊँचाई (90-120 सेंटीमीटर) के होते हैं तथा पतियाँ गहरे हरे रंग की होती हैं। तने पर बहुत कम अन्तराल पर गांठें होती हैं। जिनमें 2-3 शाखाये निकलती हैं। फल चिकने, गहरे हरे रंग के, आकर्षक तथा 5 धारियों वाले होते हैं। यह किस्म पित शिरा विषाणु रोग के प्रति अवरोधी है। औसत उपज 98 क्विंटल/हे. प्राप्त होती है।

अन्य किस्मों में पूसा मखमली, पंजाब पदिमनी, परकिन्स ग्रीन, हिसार उन्नत, हिसार नवीन, परभनी क्रान्ति तथा संकर किस्मों में डी.वी.आर-1, डी.वी.आर-2, डी.वी.आर-3, डी.वी.आर-4 आदि प्रमुख हैं।

बुवाई का समय - जायद की फसल हेतु फरवरी-मार्च तथा खरीफ की फसल हेतु जून-जुलाई का समय बुवाई के लिये उपयुक्त रहता है।

बीज की मात्रा - गर्मी की फसल हेतु 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा वर्षा की फसल हेतु 8-10 किलोग्राम/हेक्टेयर बीज की आवश्यकता रहती है।

**बुवाई की दूरी-**

मौसम लाइन से लाइन की दूरी पौधे से पौधे की दूरी

जायद फसल हेतु 45 से.मी 30 से.मी

खरीफ फसल हेतु 60 से. मी. 30 से.मी

खेत की तैयारी - भिण्डी की बुवाई के लिये 20-25 से.मी. गहरी जुताई करनी चाहिये। बीज बुवाई के समय मिट्टी भुरभरी होनी चाहिये, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा हो सके। खेत की तैयारी के समय २५ टन/हे. गोबर की सड़ी खाद का उपयोग करें।

बुवाई की विधि - भिण्डी की बुवाई मेड़ या समतल भूमि पर दोनों तरीकों से कर सकते हैं। भारी मिट्टी में मेड़ों पर बुवाई करते हैं तथा बलुई दोमट भूमि में इसकी बुवाई समतल भूमि पर करते हैं। गर्मी के दिनों में अग्रेती फसल लेने के लिए बीज का 24 घण्टे तक पानी में भिगो कर एवं छाया में थोड़ी देर सुखा कर बुवाई करते हैं। बुवाई से पूर्व कार्बोन्डिजिम

2.5-3.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित कर लेना चाहिये।

बीज की बुवाई 2.5 - 3.0 सेमी. गहराई पर करते हैं।

खाद से उर्वरक - भिण्डी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी में 20-25 टन

सड़ी गोबर की खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन की एक तिहाई मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के पहले मिट्टी में मिलाना चाहिए। नत्रजन की षेध मात्रा बुवाई के 30 -50 दिन बाद फसल में टापड्रेसिंग के रूप में दें।

सिंचाई - बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिये। इस हेतु बुवाई से पहले पलेवा कर लेना चाहिए। अच्छी फसल हेतु मौसम एवं मिट्टी के प्रकार के अनुसार आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। मार्च में 10-12 दिन अप्रैल में 7-8 दिन और मई- जून में 4-5 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। वर्षा में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा जल निकास की व्यवस्था भी करें।

अन्त सस्य क्रियायें- भिण्डी की फसल के विकास एवं बढ़वार पर खरपतवार प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु ड्यूअल (मेटालेक्जोर -50 ई.सी) की 2 लीटर मात्रा या स्टाम्प (पेन्डामेथलीन 30 ई.सी) की 3.3 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के २४ घंटे के अन्दर छिड़काव करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आवश्यकतानुसार निदाई-गुड़ाई करते रहना चाहिये।

फलों की तुड़ाई और उपज- भिण्डी की तुड़ाई समय पर नरम अवस्था में करनी चाहिये, क्योंकि कड़ा होने पर उसमें रेषे की मात्रा बढ़ जाती है। फलों की तुड़ाई फूल खिलने के 4-5 दिन बाद की जाती है तथा तुड़ाई ३-४ दिन के अन्दर पर करते रहना चाहिये। उचित देख-रेख, उन्नतशील किस्म का उपयोग, खाद एवं उर्वरकों के उचित प्रयोग से गर्मी में 8-10 टन/हे. तथा बरसात में 12-15 टन/हे. उपज प्राप्त की जा सकती है।

**प्रमुख रोग एवं नियंत्रण**

1. पित शिरा मोजेक तथा पर्ण कुन्चन- विषाणु रोग है जो सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। पत्तियों की नसे पीली पड़ जाती हैं, तथा पौधे की बढ़वार रूक जाती है। हरा भाग छिछले गड्ढों का रूप ले लेता है। पत्तियों की किनारे नीचे झुक जाते हैं। तथा कटे हुए से हो जाते हैं।

नियंत्रण रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें।

बीज को इमिडामोप्रिड (2.5 मिली/किलो बीज) से शोधित करके लगायें।

कान्फीडोर 200 एस.एल (2 मिली/लीटर पानी की दर से) रोपाई से २० दिन बाद तथा आवश्यकतानुसार १५ दिन के अन्तराल पर प्रयोग करें।

२. चूर्णा फंफूद रोग- इस बीमारी का प्रकोप होने पर पत्तियों पर गहरे भूरे रंग का चूर्ण बन जाता है, जिससे पत्तियाँ सिकुड़ कर सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम हेतु कार्बोन्डाजिम १ ग्राम/लीटर या घुलनशील गंधन 3 ग्राम/लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

**प्रमुख कीट एवं नियंत्रण**

1. फली तथा तना छेदक - इस कीट की इलियां (लारवा) फलों में छेद करके बीज को हानि पहुंचाता है। तथा तने के शीर्ष भाग को नुकसान करती है। शीर्ष भाग मुरझा जाता है तथा पौधे की बढ़वार रूक जाती है।

विधि नियंत्रण - साइपरमेथ्रीन 10 ई.सी. का 0.5 मिली/लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

2. सफेद मक्खी, जैसिड- पत्तियों का रस चुसने से पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। पीतशिरा रोग को फैलाना में सहायक है।

नियंत्रण - डायमिथीएट 30 ई.सी 1 मिली/लीटर या कांफिडोर 0.3 मिली/लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें।

3. भिण्डी की लाल माइट- गर्मी वाली भिण्डी में यह बहुत हानिकारक है। शिशु तथा प्रोढ़ पत्तियों के निचली सतह पर रस चूसते हैं। रस चूसने से पत्तियों की उपरी सतह पर पीली पतियाँ उभर आती हैं तथा पतियाँ सूख जाती हैं।

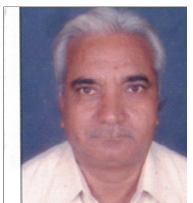
नियंत्रण - डाइकोफाल का 2.5 मिली/लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।

## (पाक्षिक राशि फल)

16-02-2014 से

28-02-2014

ज्योतिषाचार्य -पं.जयदत्त व्यास -जयपुर



AJS	पिछले समय से चल रही समस्याओं का अंत, पदप्रतिष्ठा, प्राप्ति योग,
BKT	प्रयत्नों से लाभ, मन सम्मान में वृद्धि, आर्थिक लाभ,
CLU	धन लाभ, प्रतिष्ठा, तथा शुभ फल प्राप्ति योग,
DMV	परेशानियों में निम्नता, धीरे धीरे प्रयत्नों से लाभ,
NEW	परेशानियों का अंत धन लाभ, व्यापार लाभ
FOX	धन लाभ, भूमि लाभ, प्रतिष्ठा में वृद्धि!
GPY	धन लाभ भूमि लाभ आंशिक राहत व समय!
HQZ	व्यापार लाभ, पिछले समय से चल रही बाधाओं का अंत!
IR	यात्रा योग, अधिकारियों द्वारा परेशानी, प्रतिष्ठा चिन्ता!

## गुलाब की आर्गनिक जैविक उन्नत खेती, फूल वाले पौधे

यद्यपि इसके फूल साल भर प्राप्त होते हैं लेकिन जाड़े की ऋतु में उच्च गुणवत्ता वाले एवं आकार में बड़े पुष्प प्राप्त होते हैं इसके फूलने का मुख्य समय मार्च माह है लेकिन कम तापमान होने पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक अधिक संख्या में फूल आते रहते हैं फूलों की उत्तम पैदावार के लिए प्रचुर मात्रा में धुप व आर्द्रता वाली जलवायु उपयुक्त रहती है। उचित व्यवस्था करके गुलाब की खेती सभी प्रकार की भूमियों में भली-भांति की जा सकती है लेकिन उचित जल निकास युक्त जीवांश पदार्थों की धनी बलुई दोमट से दोमट भूमि, जिसका पी.एच. मान 6-7.5 गहरी जुताइयां करके पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए।

खेत की जुताई के बाद तैयार करके क्यारियों में विभक्त कर लेते हैं फिर मई-जून माह में 50-60 से.मि. गहरे गड्ढों की उचित दुरी पर खुदाई करके 10-12 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं जिससे मिट्टी में उपस्थित कीड़े-मकोड़े फफूंदी व खरपतवार इत्यादि नष्ट हो जाते हैं 10-12 दिन बाद इन गड्ढों में 25-30 से. मि. की मोटाई में गोबर की खाद डालकर उसके बाद ऊपर से बाहर निकाली हुई मिट्टी को पुनः भर देना चाहिए सबसे ऊपर की 10-15 से.मि. मोटी पर्त में पुनः गोबर की खाद डालकर गुड़ाई कर देते हैं इसके बाद तैयार गड्ढों में पौधों को रोपित कर देते हैं।

गुलाब की किस्मों को निम्न 5 वर्गों में विभक्त किया जाता है -

**हाईब्रिड टी :-**

यह बड़े फूलों वाला महत्वपूर्ण वर्ग है इस वर्ग के पौधे झाड़ीनुमा लम्बे होते हैं इनकी विशेषता यह है की प्रत्येक शाखा पर एक फूल निकलता है जो अत्यंत सुन्दर होता है हालाँकि कुछ ऐसी किस्में भी हैं जिनमें छोटे समूह में भी फूल आगते हैं अधिक पाला पड़ने की स्थिति में कभी-कभी पौधे मर जाते हैं इस वर्ग की प्रमुख किस्में हैं एम्बेसडर अमेरिकन प्राइड, बरांडा, डबल, डिलीट, फ्रेंडशिप, सुपरस्टार, रक्त गंधा, क्रिमसनगोरी, अर्जुन, फस्टे रेड, रक्तिमा, और ग्रांडमाला आदि

**फ्लोरीबंडा :-**

इस वर्ग में आने वाली किस्मों के फूल हाईब्रिड टी किस्मों की तुलना में छोटे होते हैं और अधिक संख्या में कम लगेते हैं इस वर्ग की प्रमुख किस्में हैं - जम्बरा अरेबियन नाइट्स, रम्बा वर्ग, चरिया, आइसबर्ग, फस्टे एडिसन, लहर, बंजारन, जन्तर-मंतर, सदाबहार, प्रेमा और अरुनिमा आदि.

**पोलिथ्या :-**

इस वर्ग में आने वाली किस्मों के पौधे और फूलों का आकार हाईब्रिड टी एवं फ्लोरीबंडा वर्ग से छोटा होता है लेकिन गुच्छा आकार में फ्लोरी बंडा वर्ग से भी बड़ा होता है जैसे - चट्टीलौन व ईको आदि छोटे आते हैं जो गुच्छों में लगेते हैं एक गुच्छों में कई फूल होते हैं .

## सुवचार

आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, उतने ही अधिक लोगों के विश्वसनीय बनते हैं।

-पीट मेराविच

उन सभी कारणों को भूल जाएं कि कोई कार्य नहीं होगा आपको केवल एक अच्छा कारण खोजना है कि यह कार्य सफल होगा।

- डॉ. राबर्ट

## सूचना

पाक्षिक समाचार पत्र सृष्टि एगो में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में समाविष्ट सभी बातों की जाँच-परखकर पाना संभव नहीं है विज्ञापनों में अपने उत्पादों अथवा अपनी सेवाओं के बारे में विज्ञापनदाता जो दावे करते हैं, सृष्टि एगो समाचारपत्र उसकी कोई गारंटी नहीं लेता. विज्ञापनों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता द्वारा नहीं होती है तो उसके लिए पाक्षिक सृष्टि एगो समाचारपत्र समूह के मुद्रा, संपादक, प्रकाशक व मालिक किसी भी रूप में जवाबदेह नहीं होंगे, कृपया इसे ध्यान में रखें. अतः हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि विज्ञापन में उल्लिखित बातों के संदर्भ में कोई भी कार्र करने के पूर्व उसके बारे में आवश्यक छानबीन कर लें.

## शेखावटी उत्सव 2014 का शुभारंभ

नवलगढ़ राजस्थानी कला, संस्कृति की अनुपम छटा बिखेरने वाल 19 वें शेखावटी उत्सव 2014 का नवलगढ़ स्थित सूर्यमंडल मैदान में भव्य आतिशबाजी और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। तीन दिन तक चलने वाले उत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग, झुंझुनू जिला प्रशासन एवं मोरारकाल फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। शेखावटी उत्सव 2014 का उद्घाटन सूर्य मण्डल मैदान में झुंझुनू कलेक्टर डॉ. आरुशी मलिक के करकमलों द्वारा ढप बजाकर किया गया। समारोह की सम्मानीय अतिथियों में श्री फेलिक्स रोनाल्ड, बीडी मैनेजर, जी.आई.जेड. साउदी अरब और

नादिन ल. प्रिंस, फ्रेंच-इण्डियन कल्चर सेंटर, फतेहपुर शेखावटी, उपस्थित रहे। डॉ. आरुशी मलिक ने कहा कि फाउन्डेशन ने किसानों के लिए जो मूहिम चलाई है वो प्रशंसनीय है। ऑर्गेनिक खेती में खर्चा कम आता है और पैदावार ज्यादा होती है। किसानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए फाउन्डेशन द्वारा किये जा रहे कार्य मील के पत्थर साबित हो रहे हैं वहीं किसानों को भी जैविक उत्पादों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। श्री कमल मोरारकाल ने कहा कि लगातार 19 साल से इस उत्सव के कारण सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ा है, इस उत्सव ने शेखावटी का एक नई पहचान दी है।



## किसानों की फसलों की तारबंदी कार्य को नरेगा में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव-कृषि मंत्री

जयपुर कृषि मंत्री श्री प्रभूलाल सैनी ने राज्य विधानसभा में बताया कि किसानों की फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए 'फेन्सिंग' व तारबन्दी के कार्य को नरेगा योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। श्री सैनी ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि फसलों के तारबन्दी कार्य को नरेगा योजना की गाइडलाइन्स के तहत ही कराया जाना प्रस्तावित है। इसमें किसान द्वारा अपने हिस्से की राशि दी जायेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जल्दी ही इस पर कार्यवाही की जायेगी। कृषि मंत्री श्री प्रभूलाल सैनी ने राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि अधिक प्रीमियम के कारण जिन जिलों को मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें

संशोधित किया उन्हें संशोधित बीमा योजना में शामिल कर लाभान्वित करने का प्रयास किया जाये। श्री सैनी ने शून्यकाल में इस सज्जन्ध में उठाये गये मुद्दे में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत राज्य के 21 जिले आते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि जिन जिलों से प्रीमियम ज्यादा आता है और इस कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे जिलों का परीक्षण करवाया जाये। उन्होंने कहा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में प्रीमियम बढ़ाने का फैसला भारत सरकार द्वारा लिया गया है। इस सज्जन्ध में एक नवम्बर, 2013 को भारत सरकार ने एक परिपत्र जारी कर प्रीमियम को 4.8 प्रतिशत किया है।



## कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक-2014 ध्वनिमत से पारित

जयपुर, विधानसभा ने कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक 2014 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कृषि मंत्री श्री प्रभूलाल सैनी ने सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक लाने के कारणों एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय जोबनेर के लिए 7 जुलाई, 1947

को स्व. कर्ण नरेन्द्र सिंह ने दो हजार एक सौ एकड़ भूमि दान की और इस महाविद्यालय का नाम उनके नाम से रखा श्री सैनी ने कहा कि स्व. श्री कर्ण नरेन्द्र की स्मृति में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का नाम परिवर्तन कर इनका नाम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर रखने के लिए उनको शिक्षाविदों,

बुद्धिजीवियों, राजनैतिक नेताओं एवं सामाजिक संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय जिस भूमि पर है यह भूमि उनके द्वारा दान की गई थी इसलिए विश्वविद्यालय का नाम श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर किया जा रहा है।

## यमुना जल में राजस्थान का आवंटित हिस्सा मांगा, श्रीमती वसुन्धरा राजे

जयपुर, श्रीमती वसुन्धरा राजे ने यमुना नदी के पानी में राजस्थान का आवंटित हिस्सा दिलवाने के लिये केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद से पत्र लिखकर सकारात्मक हस्तक्षेप का आग्रह किया है। श्रीमती राजे ने लिखा है कि

यमुना के दोनों हेडवर्क्स ताजेवाला और ओखला से राजस्थान के हिस्से का पानी हरियाणा उपयोग में ले रहा है। यमुना जल समझौते के 20 साल बाद भी राजस्थान को उसका पानी नहीं मिल रहा है। अपर यमुना रिवर बोर्ड के आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान को यमुना जल में उसके 9 प्रतिशत हिस्से में से मात्र 1 प्रतिशत ही उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी तरफ, हरियाणा 48 प्रतिशत आवंटित हिस्से की बजाय 69 प्रतिशत पानी का उपयोग कर रहा है।



रिपोर्ट में राजस्थान के हक को सही माना है। यह पानी मुख्य रूप से प्रदेश के चुरू, झुंझुनू व निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए है।

## किसानों की मेहनत से तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता संभव-डॉ. जे.एस.सन्धु

भरतपुर, राई-सरसों फसल का भारतीय आर्थिक व्यवस्था में एक विशेष स्थान है। देश में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत किस्मों एवं तकनीकों को किसानों द्वारा अपनाकर तिलहनों में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना संभव है। यह बात भारत सरकार के कृषि आयुक्त डॉ. जे. एस. सन्धु ने भरतपुर जिले के उँचागाँव में कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय के संयुक्त संस्थागत सम्पर्क कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किसान मेलों में किसानों को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रख्यात पादप रोग वैज्ञानिक डॉ. पी.आर. वर्मा ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन को कीट एवं रोग काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए रोगों एवं कीटों को पहचान कर समय पर उनका नियंत्रण करें जिससे इनसे फसल में होने वाली हानि से बचा जा सके। इस अवसर पर सरसों अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. धीरज सिंह ने कहा कि देश में सरसों उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सम्पूर्ण कार्यक्रम का संचालन निदेशालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अशोक शर्मा ने किया।

## राजस्थान माल विधेयक, 2014 ध्वनि मत से पारित

जयपुर, विधानसभा ने राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 ध्वनि मत से पारित कर दिया। खाद्य एवं नारिकेल आपूर्ति मंत्री श्री हेम सिंह भडाना ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया और विधेयक लाने के पीछे के कारणों एवं

उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आम जनता के हितों एवं सुशासन के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा उन वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके, जिनकी बाजार में कीमतें बहुत हैं ताकि आम उपभोक्ता भी उनका उपयोग कर लाने के पीछे के कारणों एवं



## आम लोगों की समस्याओं का समाधान पहली प्राथमिकता : कृषि और पशुपालन मंत्री

जयपुर, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री प्रभूलाल सैनी ने कहा कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है, जहां सरकार जनता से उनके घर जाकर उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रही है और उनका समाधान कर रही है। जनसेवा यात्रा के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए श्री सैनी ने कहा कि श्रीमती वसुंधरा राजे की मंशा है कि प्रदेश के हर आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए आम लोगों की समस्या का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। श्री सैनी ने यह बात जनसेवा यात्रा के दूसरे दिन सवाईमाधोपुर जिले की बाँली पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर हुई जनसुनवाई के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि आम जनता का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, लेकिन उनका लाभ आम गरीबों को नहीं मिलता है।

## डेयरी शो हैदराबाद इंटरनेशनल में सृष्टि एगो



हैदराबाद .. डेयरी शो हैदराबाद इंटरनेशनल सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सृष्टि एगो ने डेयरी शो हैदराबाद इंटरनेशनल में भाग लिया

### SSARDAR-G Gold

(Amino Acid 15%, Nitrobenzene 18%, Humic Acid 10%)

SSardar G Gold Granules use for All Crops

### LANDKRUSHIER

Content : 25 Types of Amino Acid + Alge + Solvent  
A Balanced Systemic Bio Stimulant

### SrushtiAllcrops

Srushti Allcrops- Is a partially chelated & well balanced micro-nutrient mixture used for all type of crops, vegetable & horticulture.

### SURAKSHA

SYSTEMATIC FUNGICIDE FOR FOLIAR SPRAY

Contents : Phosphoric Acid 32% + Copper EDTA 8% + Emulsifier & Solvent 60%

### Hindchem Corporation

307, Linkway Estate, New Link Road, Malade (W), Mumbai-400054  
Website : www.hindchem.com  
Customer Care No. 0141-3130277  
हमारा प्रथम स्वस्थाल किसान

### विज्ञापन हेतु संपर्क करें

ममता ( मुंबई ) 08898600347  
गौतम राज सारस्वत ( भायंदर ) 09987030599  
महेन्द्र दर्धीच ( जयपुर ) 09462392863  
जयदीप माथुर ( गुड़गाँव ) 09928960900  
दिलबाग सिंह बडेसरा ( गुड़गाँव ) 09810026778

### राष्ट्रीय डेरी मेला

(25-27 फरवरी, 2014)

मेला स्थल : प्रदर्शनी मैदान  
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान  
करनाल

डॉ. डी.के. गोसाईं डॉ. गोपाल सांखला डॉ. बी.एस. गीणा डॉ. पी.एस. अंबियार  
9215757800 9416952786 9466242194 9729580277  
E-mail: dairymela@gmail.com, gosaindk@yahoo.com  
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल -132 001 (हरियाणा)

### कच नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा

6th  
MEGA AGRI SHOW

Janmabhoomi group of Newspaper  
**KUTCHMITRA**  
Hi-Tech  
**AGRI FAIR**  
कृषि मेला

Date : 1 To 4 March 2014  
Venue : BHUJ-KUTCH(GUJRAT)

Stall Booking  
NATIONAL RESEARCH & MANAGEMENT INSTITUTE  
204, ARIHANT CHAMBER, NR. PNB BANK, STATION ROAD, BHUJ-KUTCH GUJARAT  
MAIL : vavetar@gmail.com / nrmi1313@gmail.com www.hitechagrifair.com  
9408529283 /9712558961/9408529273

Organised  
वालेतर व्यापार व्यापार सृष्टि एगो अमृत पोती

Media Partner  
Hindi & Gujarati Edition  
GREEN PILL AGRI MEDIA tradendia.com